RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 27 SEPTEMBER TO 03 OCTOBER 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 2 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

1 अक्टूबर से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी के बजट पर पड़ेगा सीधा असर
Page 2

विशाल रक्तदान शिविर का महाकुंभ युवा उद्योगपतियों ने किया रक्तदान
Page 3

इंदौर मेट्रो का 6 किमी ट्रायल रन 30 सितंबर को, CM आएंगे
Page 5

editoria!

अक्षय ऊर्जा और भारत

भारत में पिछले कुछ वर्षों से अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए खूब प्रयास किये जा रहे हैं. इस दिशा में भारत ने कुछ लक्ष्य तय कर रखे हैं. इनमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26 वें सम्मेलन में पांच संकल्पों की घोषणा की थी, और उन्हें पंचामृत नाम दिया था. इनमें पहला संकल्प, 2030 तक गैर जीवाश्म स्त्रोतों से बिजली उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट कर देना था. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत इस लक्ष्य को 2030 की समयसीमा से पहले ही हासिल कर लेगा. ग्लासगो सम्मेलन में भारत के घोषित पांच लक्ष्यों में दूसरा 2030 तक देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 50 फीसदी हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का था. मंत्री ने कहा है कि भारत इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी तेज प्रगति कर रहा है, और यदि कोरोना महामारी की वजह से दो वर्ष का नुकसान नहीं होता तो भारत अभी तक इसे प्राप्त कर चुका होता. भारत अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ और सुरक्षित विश्व देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी यह टिप्पणी अक्षय ऊर्जा के विकास के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को रेखांकित करती है. दरअसल, दुनियाभर में उन्नति का हर लक्ष्य आज ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है. भारत में ऊर्जा की खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है. भारत की ऊर्जा जरूरत का अधिकांश हिस्सा कोयला और तेल व गैस जैसे स्त्रोतों से पूरा होता है. लेकिन जीवाश्म ईंधन के ये भंडार सीमित हैं. ऐसे में यदि विकल्पों की खोज नहीं की गयी, तो एक दिन ये भंडार समाप्त हो जायेंगे. फिर अगली पीढ़ी क्या करेगी? दुनियाभर में इसे लेकर विचार हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ कि ऊर्जा के इन साधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के साथ ऊर्जा के ऐसे स्त्रोतों पर निर्भरता बढ़ायी जायेगी जो खत्म नहीं होते हैं. ये स्त्रोत पर्यावरण के भी अनुकूल हैं और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का कारगर समाधान पेश करते हैं. भारत ने अक्षय ऊर्जा का विकास जारी रख दुनिया को संदेश दिया है कि वह आर्थिक प्रगति की राह पर जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ा रहा है. उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के अपने पांचवें और सबसे बड़े लक्ष्य को भी समय से पहले प्राप्त कर लेगा.

रूस कच्चे तेल की कम बिक्री से परेशान

भारतीय रिफाइनरों को दिया ज्यादा छूट पर खरीदने का ऑफर

नई दिल्ली। एजेंसी

रूस ने भारतीय रिफाइनरों के लिए सितंबर में कच्चे तेल की बिक्री पर छूट 25-50 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि रूस कच्चे तेल के निर्यात पर आपत्ति जता रहा था, लेकिन उनकी आपत्तियों की वजह से भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की 42 प्रतिशत से ज्यादा की बाजार हिस्सेदारी खत्म होने का खतरा था। बता दें कि सस्ते रूसी तेल ने अगस्त के सात महीने के निचले स्तर से इस महीने भारतीय खरीद में तेजी ला दी है। भारतीय तेल कंपनियों द्वारा गल्फ देशों से आयातित किए जा रहे के कच्चे तेल के तरह ही रूस के बेंचमार्क यूराल (हाई-सल्फर ग्रेड) पर छूट पिछले महीने 3- 4 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर तक गिर गई थी, लेकिन इस महीने से यह बढ़कर 5- 6 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यह जानकारी सरकारी अधिकारी और मुंबई स्थित रिफाइनर के एक अधिकारी, जो रूसी निर्यातकों के साथ बातचीत में शामिल थे, ने दी।

क्यों रूस से महंगा हो गया था कच्चे तेल का आयात

एक अन्य रिफाइनिंग अधिकारी ने कहा, भारतीय खरीदारों ने तेल व्यापारियों द्वारा सितंबर के अंत और अक्टूबर डिलीवरी के लिए अगस्त के मिड में बातचीत के दौरान बेंचमार्क रूसी यूराल (Russian Urals) ग्रेड की बिक्री पर छूट कम करने के प्रयासों का विरोध किया, जिससे व्यापारियों को छूट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कब Crude Oil बनते हैं भारतीय रिफाइनर्स के लिए प्रतिस्पर्धी?

इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा, भारतीय रिफाइनर को Urals तभी प्रतिस्पर्धी लगता है जब छूट 5 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेसिंग के लिए यूराल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए महंगे सामानों का आयात करना पड़ता है। इसके अलावा, रूसी तेल के लिए पेमेंट करना एक चुनौती बनी हुई है, ज्यादातर भुगतान अब संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में किए जा रहे हैं। 5 डॉलर प्रति बैरल से कम की छूट गल्फ देशों के कच्चे तेल को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।

रोसनेफ्ट भारत को भेजती है सबसे ज्यादा रूसी तेल

रोसनेफ्ट (Rosneft) भारत को रूसी तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। केप्लर (Kpler) के मुताबिक, इस साल रूस से भारत भेजी गई सप्लाई में इसकी हिस्सेदारी 42 प्रतिशत है। कंपनी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि क्या उसने भारतीय रिफाइनरों के लिए छूट बढ़ाई है। ज्यादातर रूसी तेल शिपमेंट बिचौलियों के माध्यम से भेजे जाते हैं।

दुनियाभर में बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के बीच भारत को होगा फायदा

ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ज्यादा छूट से भारत और भारतीय तेल कंपनियों को फायदा हो सकता है। जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें वर्तमान में 93 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 2026 तक 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अमेरिकी बैंक का अनुमान है कि 2024 में ब्रेंट की कीमतें 90-110 डॉलर प्रति बैरल और 2025 में 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेंगी, 2025 में आपूर्ति घाटा (supply deficit) 1.1 मिलियन बैरल प्रति दिन होगा, जो 2030 में बढ़कर 7.1 मिलियन बैरल प्रति दिन हो जाएगा।

पेरिस स्थित कमोडिटी इंटेलिजेंस एजेंसी केप्लर (Kpler) के आंकड़ों और रिफाइनरी इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, रूसी तेल की भारतीय खरीद अगस्त में 1.55 मिलियन बैरल प्रति दिन के मुकाबले इस महीने लगभग 1.83 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ सकती है। और ऐसा तब हो रहा है जब छूट इस साल सबसे कम थी। भारत में कच्चे तेल के आयात बाजार में रूस की हिस्सेदारी जुलाई में 43 प्रतिशत से ज्यादा थी, लेकिन छूट कम होने के बाद अगस्त में यह गिरकर 35 प्रतिशत हो गई।

Crude Oil के आयात पर बढ़ती कीमतों का कैसे पड़ता है असर? समझें

रूसी तेल आयात में वृद्धि तब हुई है जब यूरोपीय बेंचमार्क ब्रेंट (European benchmark Brent) तेल की कीमतें इस महीने 95 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं, जो 10 महीनों में उच्चतम स्तर है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि है: जुलाई की शुरुआत से कच्चे तेल में लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है।

आइये भारत की तेल आयात लागत पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के बारे में समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सालाना कच्चे तेल का आयात पिछले महीने के औसत स्तर लगभग 4.4 मिलियन बैरल प्रति दिन पर रहता है, तो भारतीय सीमा शुल्क डेटा पर आधारित गणना के अनुसार, भारत को जुलाई के शुरुआती स्तरों के मुकाबले अपने कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिदिन 90 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। सालाना आधार पर, भारत मौजूदा दरों पर तेल आयात के लिए अतिरिक्त 32 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगा।

रूसी तेल पर ज्यादा रियायत से भारत को हैं कई फायदे

रूसी तेल पर अधिक छूट से आयातित Crude Oil के लिए भारत को लागत कम करने में मदद मिलती है। इंडस्ट्री

के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय रिफाइनरों के लिए अपनी खरीद में मुनाफा पाने के लिए प्रति बैरल कुछ सेंट का अंतर भी पर्याप्त है। मुंबई स्थित एक रिफाइनर ने कहा कि छूट में प्रति बैरल 1 डॉलर की बढ़ोतरी से कई मिलियन डॉलर की बचत होती है। भारत ने इस साल रूसी तेल से 3.7-4 बिलियन डॉलर की बचत की होगी, जिससे इंडियन ऑयल के नेतृत्व वाली भारतीय राज्य-संचालित तेल कंपनियों के मार्केटिंग घाटे की भरपाई हो सकेगी।

भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, भारत ने कैलेंडर वर्ष 2023 में रूसी कच्चे तेल के लिए 69.8 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान किया है। वहीं, इराकी तेल के लिए 75 डॉलर प्रति बैरल और सऊदी अरब को कच्चे तेल के लिए 85 डॉलर प्रति बैरल का पेमेंट किया है।

G7 देशों के समूह द्वारा रूसी तेल की बिक्री पर 60 डॉलर प्रति बैरल मूल्य सीमा लागू करने के बाद रूसी निर्यातक 2023 की शुरुआत में 10 डॉलर से 13 डॉलर प्रति बैरल तक का ऑफर करते थे। इसका मतलब यह था कि फ्री ऑन बोर्ड (FOB) या लोडिंग के आधार पर मूल्य सीमा से ऊपर सप्लाई किए गए रूसी कच्चे तेल के लिए पश्चिमी शिपिंग और इन्श्योरेंस सर्विसेज उपलब्ध नहीं थीं।

निपटा लें जरूरी काम, होने वाली है 13 दिन की लंबी बैंक हड़ताल

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंकों की लंबी हड़ताल होने जा रही है। एक-दो दिन नहीं बल्कि 13 दिनों की लंबी हड़ताल होने जा रही है। 4 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने कर्मचारियों की भर्ती की मांग को लेकर 4 दिसंबर से 20 जनवरी 2024 के बीच देश भर में श्रृंखलाबद्ध हड़ताल का आह्वान किया है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि सरकार और बैंकों की ओर से बैंकों में क्लेरिकल और अधीनस्थ कैडर्स में कर्मचारियों की संख्या कम करने और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का एक जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि वे कम वर्कर चाहते हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित हों। इसी तरह हमने यह भी पाया है कि हमारे द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन के भुगतान से बचने के लिए बैंकों में नियमित और स्थायी नौकरियों को अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स करने का एक वंचित प्रयास किया जा रहा है। इसके कारण, बैंकों में लिपिक (क्लेरिकल) कर्मचारियों की भर्ती में साल-दर-साल भारी कमी आई है और अधीनस्थ कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगभग प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को उचित पारिश्रमिक के बिना अस्थायी और आकस्मिक आधार पर नियोजित किया जा रहा है। एआईबीईए ने 4-11 दिसंबर तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में हड़ताल की घोषणा की है और 2-6 जनवरी तक विभिन्न राज्यों में बैंकर काम पर हड़ताल करेंगे। इसके बाद 19-20 जनवरी, 2024 को दो दिवसीय अखिल भारतीय बैंकरों की हड़ताल होगी।

1 अक्टूबर से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी के बजट पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। एजेंसी

अक्टूबर का महीना आने में बस तीन दिन बाकी हैं।जैसे जैसे हम अक्टूबर 2023 के करीब पहुंच रहे हैं, बहुत सारे वित्तीय बदलाव हमारा इंतजार कर रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि मार्च में कौन से नए नियम लागू होंगे और वे कैसे आपके मासिक खर्च को प्रभावित कर सकते हैं।

टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम होगा लागू

सरकार एक अक्टूबर, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करने वाली है। यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएंगे। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बिना नॉमिनेशन डीमैट खाते हो जाएंगे फ्रीज

सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना जरूरी है।

आधार, पैन जमा नहीं करने पर स्मॉल सेविंग स्कीम बंद हो जाएंगी

जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NPS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का विकल्प चुना है, उन्हें 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर से खातों को निलंबित किया जा सकता है।

सरकारी नौकरियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनेगा एकल दस्तावेज

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा।

नहीं चलेगा दो हजार का नोट

एक अक्टूबर से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी दो हजार रुपये का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें. 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है।

अजरबैजान में नागोर्नो-काराबाख के तेल डिपो में विस्फोट

नई दिल्ली। एजेंसी

अजरबैजान के नागोर्नो-काराबाख में एक तेल डिपो में विस्फोट से अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। काराबाख अधिकारियों ने मंगलवार सुबह 20 लोगों के मारे जाने की सूचना दी थी। हालांकि इसके बाद पीड़ितों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब इस इलाके को छोड़कर जा रहे वहां के निवासी अपनी कारों में तेल भरवाने के लिए कतार में खड़े थे। अर्मेनियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट के पास हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के शवों को अर्मेनिया ले जाया गया है. इससे पहले मंगलवार को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) ने कहा था कि विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग झुलस गए हैं।

तीन दशक तक अलगाववादियों का शासन

बता दें कि क्षेत्र में तीन दशक तक अलगाववादियों का शासन रहा। पिछले सप्ताह अजरबैजान की सेना द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र पर पूर्ण दावा करने के बीच हजारों की तादाद में नागोर्नो-काराबाख निवासी पलायन कर आर्मेनिया पहुंच रहे हैं. इसी बीच विस्फोट की यह घटना हुई।

अजरबैजान से हारा आर्मेनिया

अजरबैजान की सेना ने पिछले हफ्ते 24 घंटे के हमले में आर्मेनिया की सेना को हरा दिया, जिससे अलगाववादी अधिकारियों को हथियार डालने पड़े और तीन दशकों के अलगाववादी शासन के बाद नागोर्नो-काराबाख के अजरबैजान में एकीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत होना पड़ा। अजरबैजान ने क्षेत्र में मूल आर्मेनियाई लोगों के अधिकारों का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जतायी है और 10 महीने की नाकाबंदी के बाद आपूर्ति बहाल करने का वादा किया है, लेकिन कई स्थानीय निवासियों को डर है कि उन्हें प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे लोग आर्मेनिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

नागोर्नो-काराबाख निवासियों का पलायन

आर्मेनिया सरकार ने कहा कि सोमवार शाम तक 6,500 से अधिक नागोर्नो-काराबाख निवासी आर्मेनिया से पलायन कर चुके हैं. रूस ने कहा कि नागोर्नो-काराबाख में रूसी शांतिरक्षक पलायन में लोगों की मदद कर रहे हैं. सोमवार रात तक शांतिरक्षकों के शिविर में करीब 700 लोग थे।

आर्मेनियाई सेना का समर्थन

नागोर्नो-काराबाख 1994 में खत्म हुई अलगाववादी लड़ाई के बाद से ही जातीय आर्मेनियाई बलों के नियंत्रण में था जिसे आर्मेनियाई सेना का समर्थन प्राप्त था। अजरबैजान ने 2020 में पूर्व में आर्मेनिया के दावे वाले अपने आसपास के क्षेत्र को फिर से नियंत्रण में ले लिया था।

ADB ने भारत के लिए घटाया ग्रोथ रेट का अनुमान

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में GDP ग्रोथ 6.3%रहने की संभावना

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ADB) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने जीडीपी अनुमानों में 0.10 पर्सेंट की कमी की है। बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4 पर्सेंट से घटाकर 6.3 पर्सेंट कर दिया है। इसकी वजह एक्सपोर्ट में सुस्ती और कृषि उत्पादन में संभावित गिरावट है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी अनुमानों में बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.7 पर्सेंट रहने का अनुमान जताया गया है। बैंक के मुताबिक, प्राइवेट इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की वजह से जीडीपी ग्रोथ में तेजी आ सकती है। एशियन डिवेलपमेंट बैंक की सितंबर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू खपत मजबूत रहने और कंज्यूमर सेंटीमेंट बेहतर होने से वित्त वर्ष 2023-4 की बाकी अवधि और अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट को सहारा मिलता रहेगा। सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से भारतीय इकनॉमी को मजबूती मिलेगी। ADB ने कहा, 'निर्यात में आ रही सुस्ती अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल हालात पैदा कर सकती है। और बारिश में अनियमितता से कृषि उपज कम होने की आशंका है। इस स्थिति में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए 6.3 पर्सेंट कर दिया गया है।

जोखिमों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मानसून की कमी के जोखिमों के बावजूद देश चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। इसका प्रमुख कारण कंपनियों की लाभप्रदता, निजी पूंजी निर्माण और बैंक ऋण वृद्धि का बेहतर होना है। वित्त मंत्रालय की अगस्त महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के पीछे मजबूत घरेलू मांग, खपत और निवेश मुख्य वजह थी। जीएसटी संग्रह, बिजली खपत, माल ढुलाई आदि जैसे विभिन्न उच्च-आवृत्ति संकेतकों में भी वृद्धि दर्ज की गई।

मासिक समीक्षा में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, अगस्त में मानसून की कमी का खरीफ एवं रबी फसलों पर असर जैसे कुछ जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक इन जोखिमों का आकलन करने की जरूरत है। हालांकि सितंबर में हुई बारिश ने अगस्त में बारिश की कमी की काफी हद तक भरपाई की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आने से अब घरेलू शेयर बाजार में भी गिरावट का जोखिम बना हुआ है। इन जोखिमों की भरपाई कंपनी लाभप्रदता, निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण, बैंक ऋण वृद्धि और निर्माण क्षेत्र में गतिविधियां कर रही हैं। वित्त मंत्रालय की मासिक समीक्षा कहती है, ''कुल मिलाकर हम इन जोखिमों के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने के अनुमान को लेकर सहज बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू निवेश की ताकत पूंजीगत व्यय पर सरकार के निरंतर जोर देने का नतीजा है। केंद्र सरकार के उपायों ने राज्यों को भी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

रिपोर्ट कहती है कि बाहरी मांग ने घरेलू वृद्धि प्रोत्साहन को पूरक बनाने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि में शुद्ध निर्यात का योगदान बढ़ गया क्योंकि सेवाओं के निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया। जुलाई एवं अगस्त के उच्च आवृत्ति संकेतकों से दूसरी तिमाही में भी वृद्धि दर की रफ्तार बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई और मुख्य मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति दोनों ही जुलाई की तुलना में कम हुई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के स्तर पर उठाए गए कई कदमों ने प्रमुख मुद्रास्फीति को 40 महीने के निचले स्तर पर लाने में मदद की। हालांकि वैश्विक स्तर पर कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी हुई है। वित्त मंत्रालय की मासिक समीक्षा रिपोर्ट कहती है कि कुछ फसलों का बफर स्टॉक बनाने, उत्पादक केंद्रों से खरीद और सब्सिडी दर पर वितरण जैसे सरकारी कदमों से अगस्त में उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई।

विशाल रक्तदान शिविर का महाकुंभ युवा उद्योगपतियों ने किया रक्तदान

इंदौर। आईपीटी नेटवक

मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंतर्गत पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज और पॉलीमर सांवेर रोड सेक्टर ई पर विशाल ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर लगाया गया बड़ी संख्या में रक्तदान करने वाले दानदाताओं का तांता लगा रहा इस अवसर पर गणेश जी की महा आरती एवं छप्पन भोग लगाया गया । रक्तदान शिविर में युवा उद्योगपति बंधुओ ने पहली बार रक्तदान किया पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज के एम डी रुचील तृप्ति दोषी ने बताया कि करीब 126 यूनिट बोतल रक्तदान हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया सांवेर रोड पर यह पहला शिविर लगाया गया कहीं उद्योगपति बंधुओ ने इस शिविर की सराहना की। शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में ब्लड डोनर रक्तदान शिविर लगाना बड़ी बात है मजदूर वर्ग में जागरूकता की कमी से वह ब्लड डोनर करने में घबराता है आपने उनका डर दूर किया अतिथि डीसीपी पुलिस मनीष अग्रवाल जी ने कहा कि रक्तदान महादान है जीवन दान देने के इस पवित्र कार्य में उद्योगपति बंधु समय निकालकर सेवा कार्य करते हैं यह समाज के लिए बड़ी बात है हम सबके लिए प्रेरणा है ए आई एम पी के अध्यक्ष योगेश मेहता ने कहा कि उद्योगपति उद्योग चलाने के साथ साथ मानव के क्षेत्र में तन मन धन से समर्पित रहते हैं उद्योगपति प्रकाश भटेवरा ने कहा कि रुचील दोषी ने सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है उसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पुण्य ही हमारे आगे आगे चलता है और साथ में जाता है औद्योगिक संगठनों की ओर से रुचिल तृप्ति दोषी का अथितियों ने स्वागत किया । तेरापंथ संघ द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के प्रेम वेद, विक्रांत नाहटा, एवं टीम द्वारा शिविर का संयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, डीसीपी पुलिस मनीष अग्रवाल, गोलू शुक्ला, संध्या यादव पार्षद, निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, दीपक जैन टीनू, जय सिंह जैन, संदीप दुबे, योगेश मेहता, प्रमोद डफरिया, बाणगंगा टीआई नीरज बिरथरे, पीयूष जैन, राजेन्द्र जैन, संजय नाहर, कपिल शर्मा, सचिन बंसल, मनीष सुराणा, रमेश महेश्वरी राजेश जैन युवा, वीरेंद्र जैन, अमित श्रीमाल, विवेक पितलिया, नीलेश सकलेचा, शैलेन्द्र नाहर, संजय छाजेड़, जतिन दीवान, कशिश दीवान, आदि कई गणमान्य नागरिक, महिलाएं उपस्थित थी कार्यक्रम का संचालन अभिषेक शेखावत ने किया एवं आभार अमित नाहटा ने माना।

जीएसटी बैठक में हो सकते ये बड़े फैसले

नतीजे डालेंगे जेब पर असर ?

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आगामी जीएसटी काउंसिल में बाजरे पर जीएसटी दर घटाने समेत 5 बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. वहीं, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर बढ़ी हुई जीएसटी दर लागू करने से जुड़े नए अपडेट जारी किए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर दरों में बदलाव की संभावना है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। पिछली बैठक 2 अगस्त को हुई थी, जिसमें कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी गई थी।

अब 7 अक्टूबर को होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाजरा यानी मोटे अनाज पर जीएसटी दरों में कटौती को लेकर फैसला ले सकती हैं। बाजरे के पैकेज्ड उत्पादों पर 5ङ्ग जीएसटी लागू है। क्योंकि, सरकार बाजरे के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, इसलिए मोटे अनाज यानी बाजरा पर जीएसटी दर घटाकर शून्य फीसदी की जा सकती है।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए नए अपडेट को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें कुछ बिंदुओं को लेकर कंपनियों ने आपत्ति जताई है। वहीं सरकार ने कई कंपनियों को जीएसटी भुगतान को लेकर नोटिस भी भेजा है। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पुनर्गठन पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ जीएसटी काउंसिल स्टील स्क्रैप पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू करने और जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर भी फैसला ले सकते हैं।

इंदौर को बनाएं एमएसएमई के माध्यम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हब

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की टीम ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की टीम से मुलाकात की एवं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे जी हेतु ज्ञापन सोंपा। उनके बिहाफ पर एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ़ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अश्विनी लाल मैडम एवं उनकी टीम से मुलाकात की एवं चर्चा की। इंदौर के लिए हर्ष का विषय है कि अश्विनी जी मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी है एवं भोपाल से ही हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि इंपोर्ट सब्सीट्यूट यानी कि जो प्रोडक्ट हम विदेशों से मांगते हैं उन्हें मध्य प्रदेश से बनाया जाए उदाहरण के लिए कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग या अन्य इसी प्रकार के उत्पाद को मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। उसके लिए मदद करेगी एवं किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए इसके लिए भी मंत्रालय को रिकमाङ करेंगी। संस्था के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने बताया कि इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। मध्य प्रदेश भारतवर्ष के हृदय में स्थित है। विदेशी उत्पादों की भी डिलीवरी यहां से 24 घंटे में देश के किसी भी कोने में हो सकती है। देश के बड़े पोर्ट और बंदरगाह जैसे नावाशेवा , कांडला और मुंद्रा इंदौर से कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित है। अतः हमारा आपसे निवेदन है की इंदौर को एक देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के 52 जिलों के उत्पादों का एक प्रदर्शन केंद्र भी इंदौर में बनाना चाहते हैं। जिसे वन डिस्ट्रिक्ट मेनी प्रोडक्ट्स के नाम से ओडीएमपी किया जा सकता है। जिसमें सूक्ष्म मध्य एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों का प्रदर्शन यहां इंदौर में किया जाएगा और सीधे विदेशी निवेशकों को इंदौर आमंत्रित कर उत्पादों को दिखाया जाएगा एवं उनके साथ खरीदी बिक्री के सौदे किए जा सकेंगे। यदि आप इसमें हमारी मदद करें तो हमारा संगठन इस कार्य को बखूबी निभा सकता है। आशा है आप हमारी मंशा को समझते हुए इस कार्य में हमारी मदद करेंगे। जिससे मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ भारत के औद्योगिक विकास को भी एक नयी गति मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर में मिले इस 'सफेद सोने' की नीलामी कराएगी सरकार,

कैसे देश की EV इंडस्ट्री को लग जाएंगे पंख

नई दिल्ली। एजेंसी

इस साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार खोजा गया था। अब सरकार इस लिथियम भंडार की जल्द नीलामी कराने जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्र ने बताया, 'जम्मू-कश्मीर में मिले लिथियम भंडार के लिए नीलामी जल्द होगी। कुछ विदेशी खनिकों ने इसमें रुचि दिखाई है।' जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में फरवरी में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा गया है। सरकार लिथियम की सप्लाई सुरक्षित करने के तरीके तलाश रही है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फायदा

लिथियम एक महत्वपूर्ण खनिज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। भारत में लिथियम भंडार मिलने से सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी। दावा किया जा रहा है कि यह भंडार भारत में लिथियम की मांग को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉकों के लिए डील

सूत्र ने यह भी कहा कि काबिल (KABIL), एक सरकारी स्वामित्व वाला जॉइंट वेंचर है, जो विदेशों में खनिजों की तलाश के लिए बनाया गया है। सूत्र ने बताया कि काबिल ने अर्जेंटीना में कुछ लिथियम ब्लॉकों को सुरक्षित करने के फाइनल स्टेज में है। सूत्र ने बताया कि लिथियम ब्लॉक सुरक्षित करने के लिए चिली सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है। यह बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। सरकार लिथियम की सप्लाई सुरक्षित करने के तरीके तलाश रही है।

क्या है काबिल?

काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना अगस्त 2019 में भारत में इस्तेमाल के लिए विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास और प्रसंस्करण के लिए की गई थी। भारत, दुनिया के टॉप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे संसाधन संपन्न देशों में प्रमुख खनिजों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी समझौते कर रहा है।

खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में पड़े पैसों का क्या होता है,

नॉमिनी, सेविंग और एफडी अकाउंट में कैसे जोड़े इसे

नई दिल्ली। एजेंसी

क्या आपने अपना बैंक खाता खोलते वक्त नॉमिनी का नाम एड किया था? क्या आपको याद है कि आपके सेविंग अकाउंट में नॉमिनी कौन है? अगर आपने अपने अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है या जोड़ना भूल गए हैं तो उसे फौरन पूरा करें। सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपके जाने के बाद आपकी जमापूंजी आपके अपनों को बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी।

खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते में पड़े उसके पैसों का क्या होता है?

अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो बैंक खाते में पड़े उसके पैसों को उसके नॉमिनी को सौंप दिया जाता है। बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद नॉमिनी की पहचान और वैरिफिकेशन के बाद खाताधारक की सारी जमापूंजी बैंक नॉमिनी को सौंप देती है।

कौन होते हैं नॉमिनी ?

जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिर एफडी करवाते हैं तो बैंक की ओर से नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। फॉर्म में इसके लिए अलग से कॉलम बना होता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो पहले समझ लें कि ये नॉमिनी होता क्या है? दरअसल नॉमिनी वो व्यक्ति होता है, जो बैंक खाताधारक के मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा या एफडी रकम को क्लेम कर सकता है।

किसे बना सकते हैं नॉमिनी?

बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में एक सेक्शन बना होता है, जहां खाताधारक को नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है। सेविंग अकाउंट के लिए आप एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।

कौन बन सकता है नॉमिनी?

नॉमिनी कोई भी बन सकता है। आप जिसपर भरोसा करते हैं, उसे अपना नॉमिनी बना सकते हैं। वो आपके परिवार का भी, आपकी पत्नी/पति, बच्चे, भाई-बहन, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको उसके अभिभावक के तौर पर एक और नाम शामिल करना होगा, जो बच्चे की ओर से रकम ले सके। अगर खाताधारक के मृत्यु तक नॉमिनी नाबालिग होता है तो बैंक उसके अभिभावक को वो रकम सौंप देती है।

अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो नॉमिनी कैसे तय होगा?

अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो सभी खाताधारकों की सहमति से नॉमिनी तय होगा। आप चाहे तो किसी का नाम नॉमिनी में जोड़ या हटा भी सकते हैं। हालांकि अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसा करने के लिए सभी जमाधारकों की सहमति जरूरी होगी।

कितनी बार जोड़ या हटा सकते हैं नॉमिनी?

आप जितनी बार चाहे उतनी बार नॉमिनी जोड़ या हटा सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सेविंग अकाउंट में क्यों जरूरी है नॉमिनी ?

सेविंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा करने से आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। अगर आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी का नाम शामिल नहीं किया है तो खाताधारक की मृत्यु के बाद फंड ट्रांसफर करने में मुश्किल होगी।

कैसे चेक करें मैंने नॉमिनी का नाम जोड़ा है कि नहीं?

आप अपने बैंक की शाखा में जाकर अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी आप नॉमिनी का नाम चेक कर सकते हैं।

क्या बाद में नॉमिनी जोड़ सकते हैं?

आप चाहे तो ऑनलाइन ही अपने नॉमिनी का नाम अपने सेविंग अकाउंट में जोड़ सकते हैं। नेटबैंकिंग के जरिए आपको ये सुविधा मिलती है। आपको लॉगइन के बाद सेविंग अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करना है। अकाउंट Summary पेज पर क्लिक कर Nominee पर क्लिक करना होगा। वहां Add new Nominee or Modify पर क्लिक कर आप नाम जोड़ या बदल सकते हैं।

बंधन रिटायरमेंट फंड का लक्ष्य निवेश किए गए पैसे पर बेहतर रिटर्न प्रदान करना

एनएफओ 28 सितंबर, 2023 को निवेश के लिए खुलेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बंधन म्यूचुअल फंड ने बंधन रिटायरमेंट फंड के लॉन्च की घोषणा की, जिसका उद्देश्य निवेशकों को उनके सेवानिवृत्ति लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए इक्विटी, डेट और अन्य निवेश माध्यमों के मिक्स में निवेश करके लंबी अवधि में निवेश किए गए पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न प्रदान करना है। फंड की प्रभावशाली एसेट आवंटन रणनीति निवेशकों को बाजार में गिरावट के दौरान संभावित गिरावट को कम करते हुए इक्विटी बाजार में तेजी से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। नया फंड ऑफर गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को निवेश के लिए खुलेगा और गुरुवार, 12 अक्टूबर, 2023 को बंद होगा। बंधन रिटायरमेंट फंड में निवेश लाइसेंस प्राप्त म्यूचुअल फंड वितरकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सीधे आनलाइन किया जा सकता है। रिटायरमेंट को लेकर योजना बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्यों है, के बारे में उपयोगी जानकारी देते हुए, श्री विशाल कपूर, सीईओ, बंधन एएमसी लिमिटेड (बंधन एएमसी) ने कहा कि "आम लोगों की औसत आयु में लगातार बढ़ोतरी, जीवन यापन की बढ़ती लागत और बढ़ती हेल्थकेयर मुद्रास्फीति निवेशकों की बचत को कम कर सकती है, जिससे रिटायरमेंट की योजना बनाना प्रासंगिक हो जाता है।"

उनका कहना है कि "आम तौर पर, रिटायरमेंट योजना बनाने के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले निवेशक मुद्रास्फीति को मात देने के लिए संघर्ष करते हैं, और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए धन की कमी का सामना करते हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद समान जीवन स्तर बनाए रखना जरूरी है, लेकिन तैयारियों की कमी एक बड़ी रिटायरमेंट फंड बनाने की यात्रा को पटरी से उतार सकती है। म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट योजना के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जो सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से निवेश करने की लचीलापन प्रदान करता है। इसके साथ ही एकमुश्त माध्यम, अपेक्षाकृत हाई ग्रोथ क्षमता का लाभ प्रदान करता है। जो निवेशक एक ऐसे रिटायरमेंट उत्पाद की तलाश में हैं जो डायवर्सिफिकेशन, टैक्स में राहत और लंबी अवधि में मुद्रास्फीति को मात देने की क्षमता के लाभों को जोड़ता है, वह बंधन रिटायरमेंट फंड में निवेश करने पर विचार कर सकता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि निवेशक बंधन रिटायरमेंट फंड में निवेश करने पर विचार क्यों कर सकते हैं, बंधन एएमसी के फंड मैनेजर, श्री विराज कुलकर्णी ने कहा कि "बंधन रिटायरमेंट फंड बाजार में तेजी के दौरान इक्विटी और डेट में प्रभावशाली आवंटन के लिए एक मॉडल-आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है ताकि बाजार में संभावित गिरावट के असर को कम किया जा सके। इस मात्रात्मक मॉडल में निवेशकों के लिए आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए वैल्यूएशन, फंडामेंटल और तकनीकी मापदंडों का एक मजबूत कॉम्बीनेशन है। यह फंड निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद उनकी नकदी प्रवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) मार्ग चुनने की भी अनुमति देता है। फंड की पांच साल की लॉक-इन अवधि निवेशकों की भावनाओं को काबू में रखेगी, जिससे उन्हें काफी लंबी अवधि तक निवेशित रहने और कम्पाउंडेड लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बंधन रिटायरमेंट फंड का इक्विटी निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ट्राजेक्ट्री और उचित वैल्यूएशन वाली क्वालिटी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इक्विटी टैक्सेशन पूरी हो, हेज्ड इक्विटी आवंटन में निवेश के साथ 65 प्रतिशत की न्यूनतम इक्विटी होल्डिंग आवश्यकता को बनाए रखा जाएगा। डेट पोर्टफोलियो को जीसेक, एसडीएल, कॉरपोरेट बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गुणवत्ता वाले उपकरणों में विविध किया जाएगा।

भारत के एक फैसले से बिगड़ जाएगा कनाडा का 'स्वाद'

कई चीजों के लिए तरस जाएंगे, दांव पर लगे अरबों रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

खालिस्तान के मुद्दे पर अपने एक बयान से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने पुराने संबंधों में खटास पैदा कर दी है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में आई दरार का कारोबार पर भी असर दिखने लगा है। कारोबार से लेकर बाजार पर इस मन मुटाव का असर दिख रहा है। अगर ऐसे ही जारी रहा तो दोनों देशों की इकॉनमी पर भी इसका असर दिखने लगेगा। अगर ये कड़वाहट इसी तरह से बढ़ती चली गई तो दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात प्रभावित होगा। जहां भारत में दाल से लेकर उर्वरक और कृषि उपकरणों पर असर हो सकता है तो वहीं कनाडा को इससे भी बड़ा झटका लगेगा। ऐसी कई चीजें है, जिसके लिए कनाडा भारत पर निर्भर है। बिस्किट, गुड़, चीनी से लेकर कई खाने-पीने की चीजों के लिए कनाडा की निर्भरता भारत पर है। अगर दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आई तो कनाडा इन चीजों के लिए तरस जाएगा।

कनाडा को लगेगा झटका

दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों का असर आयात-निर्यात पर पड़ेगा। अगर संबंध बिगड़े तो कनाडा में चीनी, गुड़ जैसी चीजों का इम्पोर्ट बंद हो जाएगा। भारत और कनाडा के संबंधों में आ रही कड़वाहट अगर बढ़ गई तो कनाडा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कनाडा भारत से आटा बिस्कुट, रस, गुड, चीनी, गजक, रेवड़ी , सर्दियों के कपड़े, हैंडटूल, गार्डनिंग टूल की डिमांड भी काफी है। अगर भारत से कारोबार बंद हुआ तो कनाडा इन चीजों के लिए तरस जाएगा। इसके अलावा कनाडा नेचुरल शहद, इलायची, मीठे बिस्कुट,अगरबत्ती,हैंडबैग,सिंथेटिक स्टेपल फाइबर यार्न, टी-शर्ट, टैक्सटाइल सूट, कंबल और विंटर वियर, ऑटो पार्टस, लकड़ी के प्रोडक्ट्स के लिए भारत पर निर्भर है।

किस पर कितना पड़ेगा असर

अगर व्यापार रुका तो असर दोनों देशों पर होगा। अब ये देखना होगा कि किसपर कितना असर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक वर्ल्ड इकॉनमी रैंकिंग 2023 लिस्ट के मुताबिक भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। भारत 3.469 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो भारत ने अगले कुछ सालों में तीसरे पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस लिस्ट में कनाडा नौवें नंबर पर है। ऐसे में अगर कारोबार पर असर पड़ा तो भारत के लिए इस झटके से उभरना कनाडा के मुकाबले आसान होगा। भारत और कनाडा के बीच आयात-निर्यात का आंकड़ा लगभग बराबर है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामना निर्यात किया था। वहीं कनाडा ने भारत को साल 2022-23 में 4.05 अरब डॉलर का सामना निर्यात किया था।

कनाडा की इकॉनमी में भारतीयों का दबदबा

कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय बसे हैं। वहां की इकॉनमी में भारतीयों का बड़ा असर रहा है। कनाडा के प्रॉपर्टी, आईटी और रिसर्च, ट्रैवेल और स्मॉल बिजनेस में सेक्टर में भारतीयों का दबदबा है। कनाडा में प्रॉपर्टी के मामले में सबसे ज्यादा भारतीय निवेश करते हैं। वहीं भारतीय छात्र कनाडा की इकॉनमी में गहरा प्रभाव डालते हैं। भारतीय छात्रों से कनाडा को हर साल सिर्फ फीस के तौर पर 75 हजार करोड़ रुपये का योगदान मिलता है।

कच्चा तेल 95 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड पिछले 24 घंटे में उछलकर 95 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीतमों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये, डीजल 92.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.86 डॉलर यानी 0.92 फीसदी उछलकर 94.82 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.85 डॉलर यानी 0.94 फीसदी की बढ़त के साथ 91.24 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

अब भारतीय ग्राहकों ने भी दिया चीन को तगड़ा झटका, पहली बार हो रहा है ऐसा

नई दिल्ली। एजेंसी

आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे चीन को भारतीय ग्राहकों ने भी तगड़ा झटका दिया है। भारत के टेलीविजन सेगमेंट में चीनी ब्रांड्स का मार्केट शेयर पहली बार घट रहा है। स्मार्टफोन के बाजार में भी यही हाल है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि जल्दी ही चीन के ब्रांड्स को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में भारत के टेलीविजन सेगमेंट में चाइनीज ब्रांड्स की हिस्सेदारी गिरकर 33.6 परसेंट रह गई है जो एक साल पहले 35.7 परसेंट थी। जुलाई और अगस्त में इसमें और गिरावट आने की संभावना है। माना जा रहा है कि 30 परसेंट तक गिर सकती है।

जानकारों के मुताबिक एलजी और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स भारत में अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। दक्षिण कोरिया की ये कंपनियां एंट्री लेवल पर कीमतों में कमी कर रही हैं जबकि चीन की कंपनियां कम कीमत वाली कैटगरी से अपना फोकस हटा रही हैं। इंडस्ट्री के तीन सूत्रों ने कहा कि वनप्लस और रियलमी जैसे चाइनीज ब्रांड्स जल्दी ही भारत के टेलीविजन बिजनस के बाहर हो सकते हैं या अपना कारोबार सीमित कर सकते हैं। इस बारे में वनप्लस और रियलमी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया।

क्यों घर रही हिस्सेदारी

मार्केट रिसर्चर काउंटरपॉइंट टेक्नोलॉजी के हालिया डेटा के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में टीवी शिपमेंट्स में चीनी ब्रांड्स की हिस्सेदारी 33.6 परसेंट रह गई है जो पिछले साल इस दौरान 35.7 परसेंट थी। जुलाई और अगस्त में इसमें और गिरावट आई है। काउंटरपॉइंट की सीनियर एनालिस्ट अंशिका जैन ने कहा कि लोग अब सैमसंग, एलजी और सोनी के मिड-सेगमेंट और प्रीमियम मॉडल्स को पसंद कर रहे हैं। साथ ही ग्राहकों की सैनसुई और एसर जैसे ब्रांड्स में भी दिलचस्पी बढ़ रही है।

इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन ग्रेट ईस्टर्न रिटेल के डायरेक्टर Pulkit Baid ने कहा कि टेलीविजन मार्केट में कंसोलिडेशन और करेक्शन का दौर चल रहा है। लॉयड जैसे ब्रांड्स आक्रामक नीति अपना रहे हैं और चीनी ब्रांड्स अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। स्मार्टफोन बाजार में भी चीनी ब्रांड्स पिछली चार तिमाहियों से मार्केट शेयर खो रहे हैं। वे एंट्री लेवल सेगमेंट से निकल रहे हैं। हाल तक 7,000 से 8,000 रुपये से नीचे की कैटगरी में चीन की कंपनियों का दबदबा था। अब वे अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए सैमसंग, ऐपल और दूसरी कंपनियों के साथ मिड से प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं।

कैसे कब्जाया मार्केट

हालांकि स्मार्टफोन मार्केट में अब भी चीनी ब्रांड्स का दबदबा है। टीवी सेगमेंट में चाइनीज ब्रांड्स की संख्या कम है जिससे दूसरी कंपनियों को हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिला है। लेकिन स्मार्टफोन बाजार में उनकी अहम हिस्सेदारी है। शाओमी, वनप्लस, रियलमी, टीसीएल और iFfalcon ने 2017-18 में भारतीय मार्केट में तहलका मचा दिया था। इन कंपनियों ने एलजी, सैमसंग और सोनी से 30 से 50 परसेंट सस्ते मॉडल उतारे थे और जल्दी ही मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली थी। इससे कई बड़े ब्रांड्स ने एंट्री लेवल सेगमेंट से किनारा कर लिया था।

भारत में कोडक, थॉमसन और Blaupunkt टीवी ब्रांड्स को बेचने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी एसएसपीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव अवनीत सिंह मारवाह कहते हैं, 'चाइनीज टीवी ब्रांड्स की स्ट्रैटजी कीमतों में कटौती करके जल्दी से मार्केट कब्जाने की थी। इससे उनका नुकसान बढ़ गया। अब वे टीवी सेगमेंट से बाहर निकलने या उस पर कम फोकस करने की रणनीति अपना रही हैं। उनका जोर स्मार्टफोन बाजार पर है। भारत में वे जिस तरह के ब्रांड्स बेचते हैं, उसमें काफी संभावनाएं हैं।'

देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की हुई शुरुआत

क्या होगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। भारत को डीकार्बोनाइजेशन टार्गेट को पूरा करने में मदद करने की आपार क्षमता है। साल 2050 तक हाइड्रोजन की ग्लोबल मांग चार से सात गुना बढ़कर 500-800 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 15 और फ्यूल सेल बसें चलाने की योजना बना रही है। पॉल्यूशन कम करने के लिए देश भर में कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में हाइड्रोजन बस का आना बड़ी राहत दे सकता है।

ट्रायल के तौर पर हुई शुरुआत

बता दें कि अभी शुरुआत में सिर्फ दो बसों को ट्रायल के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये हाइड्रोजन बसें 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन से चलने वाली ये बसें एक बार में करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर पाएंगी। पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की वजह से प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे रोकने की पहल में देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बसों की शुरुआत की गई है। इस बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इथेनॉल और दूसरे ऑप्शनल फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल्स पर भी फोकस किया जा रहा है।

पॉल्यूशन होगा कम

असल में ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूवल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो-कार्बन फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। भारत आने वाले बीस सालों में दुनियाभर की 25 प्रतिशत एनर्जी की डिमांड करने वाला देश बन जाएगा। ऑप्शनल फ्यूल के इस्तेमाल के बाद हमारा देश आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट में सबसे आगे होगा।

कैसे काम करती है हाइड्रोजन बस

हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन मिश्रण, इलेक्ट्रोलाइज़र आधारित प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जैव-मार्गों को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजनाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईंधन सेल बस को बिजली देने के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट पानी है। इसलिए यह पारंपरिक बसों जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं उनके मुकाबले पर्यावरण के काफी अनुकूल है।

इंदौर मेट्रो का 6 किमी ट्रायल रन 30 सितंबर को, CM आएंगे

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर मेट्रो रेल का ट्रायल रन 14 सितंबर को होना था, लेकिन अब यह 30 सितंबर को होगा। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रायल रन के रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन सज धजकर तैयार हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस ट्रायल रन की शुरुआत करेंगे। मेट्रो के गांधीनगर डिपो से सुपर कारिडोर स्टेशन के 3 नंबर स्टेशन तक यह ट्रायल रन होगा, जिसकी दूसरी 5.9 किलोमीटर है।

इस बीच मेट्रो का कई बार सेफ्टी टेस्ट हो चुका है। बताया गया कि ट्रायल रन के दौरान मुख्यमंत्री पीथमपुर से उज्जैन के महाकाल मंदिर तक रैपिड रेल ट्रांजिस्ट सिस्टम (RRTS) की घोषणा करेंगे। यह रूट पीथमपुर से राजवाड़ा, लवकुश चौराहा होते हुए महाकाल मंदिर तक जाएगा। ट्रायल रन से पहले मेट्रो रेल को डायनामिक टेस्ट के अंतर्गत 13 सितंबर को वायडक्ट पर ले जाया गया। ट्रेन को ट्रायल रनसे पहले दो-तीन बार उसी रूट पर चलाया जाएगा। ट्रायल के दौरान ट्रेन की रफ्तार 10 से 15 किमी प्रतिघंटा रखी जाएगी। ट्रायल के लिए गांधीनगर और सुपर कारिडोर के स्टेशन नंबर 3 के प्लेटफार्म पर शेड का काम पूरा हो गया। गांधीनगर स्टेशन पर एस्केलेटर, सीढ़ियां, आने और जाने के अलग-अलग गेट भी बनकर तैयार हैं। अब फाइनल टचिंग चल रही है।

पीथमपुर से महाकाल तक जाएगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन कंसल्टेंट (DMRC) ने पीथमपुर से राऊ तक के आरआरटीएस के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। उनके मुताबिक शहरी रूट मेट्रो का हिस्सा होगा। पीथमपुर से राऊ और वहां से राजवाड़ा होते हुए लवकुश चौराहे तक आरआरटीएस इंदौर मेट्रो का हिस्सा होगा। इसके बाद लवकुश चौराहे से उज्जैन के महाकाल मंदिर तक आरआरटीएस का रूट होगा।

इंदौर मेट्रो और आरआरटीएस जुड़ेंगे

पीथमपुर से राऊतक की दूरी 29 किमी है, जो आरआरटीएस के तहत बनाया जाएगा। फिर राऊ से राजवाड़ा होते हुए लवकुश चौराहे की दूरी करीब 15 किमी है, जो इंदौर मेट्रो के तहत बनेगा। उसके बाद लवकुश चौराहे से महाकाल मंदिर की 49 किमी रूट आरआरटीएस में बनेगा। मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के टेक्निकल डायरेक्टर शोभित टंडन के मुताबिक ट्रायल रन को लेकर तैयारी पूरी हो गई गई। प्लेटफार्म पर सफाई और सजावट का काम अंतिम चरण में है। अब आयोजन की तैयारी शुरू हो गई।

कैसे बनते हैं सीवीडी डायमंड्स जिनके लिए सूरत में मच गई 'लूट'

नई दिल्ली। एजेंसी

गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में रविवार सुबह अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। शहर के मिनी बाजार इलाके में करीब 300 लोग अचानक सड़कों की खाक छानने लगे। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि एक हीरा कारोबारी ने सड़कों पर हीरे (सीवीडी डायमंड) बिखेर दिए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। बताया गया कि सीवीडी डायमंड की कीमत में 30 परसेंट गिरावट से परेशान कारोबारी ने ऐसा किया। फिर क्या थी मिनटों में सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए और हीरे खोजने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि ये हीरे प्लास्टिक के थे जिनका इस्तेमाल नकली गहनों में होता है। आइए जानते हैं कि सीवीडी हीरे क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है।

HPHT वर्सेज CVD

लैब में हीरा दो तरह से बनाया जाता है। हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर (HPHT) मेथड और सीवीडी (केमिकल वेपर डिपोजिशन) मेथड। एचपीएचटी विधि में नेचुरल डायमंड की तरह प्रोसेस से हीरा बनाया जाता है। इसमें डायमंड सीड को चैंबर में रखा जाता है और उस पर करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60,000 एटमॉस्फीयर का प्रेशर डाला जाता है। यानी इसमें वही परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जो असली हीरे को बनाती हैं। दूसरी ओर सीवीडी डायमंड को केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरएक्शन के जरिए तैयार किया जाता है।

नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड

लैब ग्रोन डायमंड को प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। देखने में ये भी असली कुदरती डायमंड्स जैसे दिखते हैं। दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी एक ही होता है। यानी जिन पदार्थ से हीरे बनते हैं, वह भी एक जैसा होता है। लेकिन लैब में बने हीरे जहां एक से चार हफ्ते में तैयार हो जाते हैं, वहीं कुदरती हीरे धरती के गर्भ में लाखों साल की प्रोसेस में बनते हैं। इन्हें माइनिंग के जरिए निकाला जाता है। लैब में हीरे एक से चार हफ्तों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें भी सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है।

कीमत में अंतर

एक कैरेट कुदरती हीरा जहां चार लाख रुपये का मिलेगा। वहीं, लैब में बना इतने ही कैरेट का डायमंड आपको एक से 1.50 लाख रुपये में मिल जाएगा। सस्ता होने के कारण आज लैब ग्रोन डायमंड्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। लैब में बना हीरा भी सेम कलर, सेम कटिंग, सेम डिजाइन और सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा।

रीसेल वैल्यू

विदेशों में लैब में बने डायमंड की रीसेल वैल्यू 60-70% तक भी है, क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि भारत में भी डिमांड आएगी तो इसका बड़ा मार्केट होगा और रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी। बाजार बिक रहे डायमंड में लैब ग्रोन डायमंड का शेयर 30 पर्सेंट के आसपास है।

कैसे करें पहचान?

कुदरती और लैब में बने डायमंड में फर्क करना मुश्किल है। दोनों में अंतर यही है कि लैब ग्रोन डायमंड में नाइट्रोजन नहीं है, जबकि नेचुरल डायमंड में नाइट्रोजन होता है। लैब ग्रोन डायमंड खरीदने के वक्त उर्ई का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, ताकि आपको क्वॉलिटी और रीसेल वैल्यू मिल सके।

राहु अशुभ ही नहीं शुभ भी, 18 साल महादशा चलने पर इन राशियों की चमकती है किस्मत

वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के पूरे जीवन में ग्रह-नक्षत्रों का विशेष प्रभाव होता है। ग्रहों की चाल और दशा का प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक व्यक्ति के ऊपर सभी 9 ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चलती है। जिसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही हो तो वह ग्रह अगर व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थान पर विराजमान है तो व्यक्ति को शुभ फल ही मिलते हैं, वहीं अगर ग्रह कुंडली में गलत स्थान पर हैं व्यक्ति को अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। हर एक ग्रह की महादशा और अंतर्दशा अलग-अलग होती है। आज हम आपको पापी ग्रह समझे जानें वाले राहु के महादशा के बारे में बताने जा रहे हैं। राहु ग्रह की महादशा किसी व्यक्ति के ऊपर करीब 18 साल तक रहती है। आइए जानते हैं राहु की महादशा चलने पर कब-कब और कैसा प्रभाव देखने को मिलता है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

18 साल राहु की महादशा और कुंडली में राहु के शुभ होने का प्रभाव

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का महादशा 18 साल तक चलती है ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में राहु शुभ स्थान पर विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ कई तरह की उपलब्धियों को हासिल करता है। समाज में मान-सम्मान ऊंचे स्तर का होता है। ऐसे लोग राजनीति में ऊंचे मुकाम को हासिल करते हैं। कुंडली में राहु के शुभ होने पर व्यक्ति खुफिया कार्यों में लगा रहता है।

कुंडली में राहु अशुभ होने पर

वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में राहु के अशुभ होने पर और महादशा चलने पर व्यक्ति को बुरे परिणाम की प्राप्ति होती है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति बुरी संगत और आदतों में फंसा रहता है। अशुभ राहु के प्रभाव से व्यक्ति दूसरों से छल और कपट का सहारा लेता है। राहु के अशुभ होने पर व्यक्ति नशाखोरी और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त रहता है। ऐसे लोगों का मन भगवान की आराधना में कम लगता है। कुंडली में राहु के अशुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में बदनामी मिलती है।

राहु की प्रिय राशियां

राहु ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों को किसी न किसी राशि पर आधिपत्य जरूर होता है। इसके अलावा राहु-केतु हमेशा ही उल्टी चाल से चलते हैं। राहु शनिदेव के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे में राहु ग्रह हमेशा ही मकर और कुंभ राशि पर मेहरबान रहते हैं। मकर और कुंभ राशि शनिदेव के स्वामित्व वाली राशियां होती है।

मंगलादित्य योग के महासंयोग में महालय श्राद्ध पक्ष होगा शुरू

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

पितरों का श्रद्धा तर्पण करने का पितृपक्ष तथा कनागत 29 सितंबर से प्रारंभ होगा। पूर्णिमा से शुरू होने वाला यह पितृपक्ष सर्व पितृ अमावस्या शनिचरी अमावस्या 14 अक्टूबर को पूर्ण होगा। 16 दिनों तक होने वाले श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज के साथ, पशु पक्षियों की सेवा भोजन के साथ पितरों की याद में पेड़ पौधों को लगाने का भी विधान है। क्योंकि पितरों को नदी, तालाब और जलाशय में पितृ तर्पण, पिंडदान देने की परंपरा प्राकृतिक संरक्षण से जुड़ी है, इस बार श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिन का रहेगा। वहीं पंचक नक्षत्र में श्रद्धापक्ष प्रारंभ होने से श्राद्धकर्ता को पांच गुना शुभ फल प्रदान करेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार श्राद्ध पक्ष का आरंभ 29 सितंबर शुक्रवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वृद्धि योग वव करण तथा मीन राशि के चंद्रमा में शुरू होगा। इसके साथ ही श्रद्धा आरंभ में सूर्य, मंगल के कन्या राशि पर गोचर होने का साक्षी रहेगा। वहीं 29 तारीख की मध्य रात्रि में अमृत सिद्धि योग का संयोग बनेगा। जो अगले दिन सुबह तक रहेगा।अमृत सिद्धि योग के संयोग में पितरों के निमित्त किया गया। तर्पण व पिंडदान उन्हें अमृत प्रदान करेगा।

श्राद्ध पक्ष में सूर्य, चंद्र का सम सप्तक दृष्टि संबंध से कुंजर छाया योग

ज्योतिष ग्रंथ निर्णय सिंधु व अन्य ग्रंथौ के साथ वैज्ञानिक पक्ष को देखने से इस बार श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा और अमावस्या पर कुंजर छाया योग बनेगा। जो की अद्भुत होगा। यह योग केंद्र की गणना से बनेगा। वहीं कर्म पुराण में बताया गया है। कि पितृपक्ष में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मंत्र शुद्ध होना चाहिए। तथा इन दिनों अपने पितरों को तुलसी अवश्य चढ़ाने चाहिए। क्योंकि पितर तुलसी की गंध से शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

पितृपक्ष में भूलकर भी न करें मांगलिक कार्य, वंश पर पड़ता है अशुभ प्रभाव!

30 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है. पुरे 15 दिनों तक पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शान्ति के लिये पिंडदान, तर्पण, ओर श्राद्ध किया जाएगा. मान्यता है कि पूरे एक वर्ष में यही 15 दिन ऐसा होता है, जब पितृ धरती पर आते हैं. भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से शुरुआत होकर अश्विन माह के अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है. जिन परिवार के सदस्यों का देहांत हो जाता है, उन्हें पितृ मानते हैं. इन 15 दिनों में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं. वहीं पितृपक्ष जैसे ही शुरू होता है सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं. आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में क्या वर्जित होता है और क्यों?

पितृपक्ष में ना करें ये कार्य

पितृपक्ष के दिनों मे लोग पितृ के लिये शोक में रहते हैं. उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिये पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है. अब शोक के दिनों में कोई भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे, मुंडन, जनेऊ, गृहप्रवेश, हवन, कथा आदि कराना उचित नहीं होता है. ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और घर पर अशुभ प्रभाव पड़ता है. वहीं पितृपक्ष में कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए. इसके साथ नया वाहन, जमीन, फ्लैट, घर की छत की ढलाई भी नहीं करनी चाहिए. इससे वंश पर अशुभ प्रभाव पड़ता है.

क्यों खास है पितृ पक्ष ?

ज्योतिषाचार्य बताते है कि पितृपक्ष को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है. मान्यता है कि यमराज भी श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वह स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ओर पिंडदान ग्रहण कर सके. पितृपक्ष के दिनों मे पितरों को तर्पण और श्राद्धकर्म करने से उनका मोक्ष की प्राप्ति होती है. वही पीतर प्रसन्न होकर अपने वंश को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. पितृ पक्ष के दिनों में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वज को जल देने का विधान है.

अनंत चतुर्दशी पर क्या है 14 गाठों वाले सूत्र का राज, पढ़ें इसका महत्व और रक्षासूत्र बांधने की विधि

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले सूत्र में 14 गांठ होती है। यह सूत्र पहले भगवान विष्णु को बांधा जाता है। फिर स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य को यह रक्षा सूत्र बांध सकते हैं।

सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन श्रीहरि की पूजा करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र बांधना चाहिए।

अनंत चतुर्दशी पर रक्षा सूत्र बांधने का महत्व

अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले सूत्र में 14 गांठ होती है। यह सूत्र पहले भगवान विष्णु को बांधा जाता है। फिर स्वयं के या परिवार के किसी सदस्य को यह रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र के गांठ चौदह लोगों का प्रतीक मानी जाती है। हर गांठ एक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा गांठे भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक है। जो जातक इस दिन श्रीहरि को रक्षा सूत्र बांधता है, उसे 14 लोकों के सभी सुख प्राप्त होते हैं। 14 सहस्त्र पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं।

अनंत चतुर्दशी पर रक्षा सूत्र को बांधने की विधि

अनंत चतुर्दशी पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र रेशम या कपास से बना होता है। रक्षा सूत्र को दूध में भिगोना चाहिए। फिर उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर पूजा-पाठ करें। आप रक्षा सूत्र भगवान विष्णु को बांध सकते हैं या उनके चरणों में रख सकते हैं। नित्य पूजाकर्म करने के रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने से ग्रह शांत होते हैं। सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है।

खाने में खुश्बू बिखेरने और जायका बढ़ाने वाली हींग

भारत में जल्द होने लगेगा उत्पादन

नई दिल्ली। एजेंसी

पके घर में शाकाहारी खाना खाया जाता हो या मांसाहारी, हर तरह के व्यंजन बनाने में हींग का इस्तेमाल होता ही है। इसमें ना सिर्फ तेज खुश्बू होती है, बल्कि जारी सी हींग खाने का जायका भी बदल देती है। ये भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान समेत कई देशों की रसोई में इस्तेमाल होने वाला जरूरी मसाला है। ये खुश्बू और जायका बढ़ाने के साथ ही खाने को पचाने में भी मददगार की तरह काम करता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि भारत में अब तक इसका उत्पादन नहीं होता है? क्या आप जानते हैं कि छोटे-बड़े कंकड़ों जैसी दिखने वाली हींग तैयार कैसे होती है?

भारत में हींग का उत्पादन तो क्या, इसका पौधा लगाने के लिए बीज तक नहीं मिलता है। इसलिए भारत में इस्तेमाल होने वाली शत-प्रतिशत हींग का आयात करना पड़ता है। जबकि, दुनिया में हींग की कुल खपत का 50 फीसदी हिस्सा भारतीय रसोइयों में ही इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि हम हर साल 940 करोड़ रुपये मूल्य की 1500 टन हींग आयात करते हैं। यही नहीं, भारत के हर घर में इस्तेमाल होने वाली सौ फीसदी हींग मुस्लिम देशों से आयात की जाती है। हम अपनी खपत का 90 फीसदी हिस्सा अफगानिस्तान, 8 फीसदी उज्बेकिस्तान और 2 फीसदी ईरान से आयात करते हैं।

कैसे किया जाता है हींग का उत्पादन?

हींग फेरुला एसाफोइटीडा नाम के पौधे की जड़ से निकाले गए रस से तैयार किया जाता है। हींग का उत्पादन आसान नहीं होता है। दरअसल, सबसे पहले फेरुला एसाफोइटीडा की जड़ों से रस निकाला जाता है। इसके बाद पर्याप्त मात्रा में रस इकट्ठा होने पर हींग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। हींग काबुली सफेद और हींग लाल दो तरह की होती है। इनमें सफेद हींग पानी में आसानी से घुल जाती है। वहीं, लाल या काली हींग तेल में घुलती है। कच्चे हींग की गंध और स्वाद बहुत तीखी होती है। इसलिए कच्ची हींग खाने लायक नहीं मानी जाती है। पौधे की जड़ से निकाले गए रस को खाने लायक गोंद और स्टार्च में मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तैयार की जाती है। हींग के पौधे की जड़ से निकाले गए रस को पिसे हुए चावल में मिलाकर भी तैयार किया जाता है।

कैसे होती है एसाफोइटीडा की खेती?

फेरुला एसाफोइटीडा यानी हींग उत्पादन के लिए रस उपलब्ध कराने वाले पौधे को पनपने और फलने-फूलने के लिए बेहद ठंडा वातावरण चाहिए होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही बर्दाश्त कर सकता है। हींग के पौधे को तैयार होने में 4 से 5 साल का लंबा वक्त लगता है। वहीं, पूरी तरह तैयार होने के बाद इसकी जड़ों से करीब-करीब 500 ग्राम हींग निकाला जा सकता है। बाजार में बिक्री के आने वाली तैयार हींग की कीमत 35 से 40 हजार रुपये प्रति किग्रा तक है। इसकी खेती के लिए ऐसी जगह होना जरूरी है, जहां पानी ठहर ना सके। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, हींग के पौधों कम नमी वाले और अत्याधिक ठंडे इलाकों में बड़े पैमाने पर लगाए जा सकते हैं।

इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है हींग?

हींग का पौधा गाजर और मूली की श्रेणी में आता है। लिहाजा, ठंडे और शुष्क वातावरण में इसकी पैदावार सबसे अच्छी होती है। दुनियाभर में हींग की 130 किस्में पाई जाती हैं. इनमें से कुछ किस्में पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पहले से उपजाई जाती है। हालांकि, फेरुला एसाफोइटीडा किस्म भारत में नहीं पाई जाती है। भारतीय रसोइयों में इसी किस्म की हींग का इस्तेमाल होता है. इसीलिए इसका आयात करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि हींग बाजार में इतने ऊंचे दाम पर क्यों मिलती है? दरअसल, इसका पौधा तैयार होने में ही चार से पांच साल लगते हैं। फिर एक पौधे की जड़ से महज 500 ग्राम तक ही रस निकल सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर पौधे से रस मिले ही जाए। इसीलिए भारत में अच्छी क्वालिटी की हींग की कीमत 40 रुपये प्रति किग्रा तक है।

हींग की कीमत पर किन चीजों का असर?

हींग की कीमत इस बात पर भी निर्भर करती है कि इसे किस तरह से तैयार किया जा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक, हींग की कीमत उत्पादन के समय रस में मिलाई गई सामग्री पर भी निर्भर करती है। हींग को तैयार करने के लिए उसके रस में चावल पाउडर, हींग पाउडर समेत कई चीजें मिलाई जाती हैं। वहीं, हींग पाउडर की कीमत हींग क्रिस्टल से कम होती है। दक्षिण भारत में हींग को पकाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर का मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। हींग की ऊंची कीमतों और भारी-भरकम आयात के कारण कुछ साल पहले भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने फेरुला एसाफोइटीडा को भारत में उगाने के लिए शोध कार्य करना शुरू किया था।

भारत में कहां लगाए गए हैं हींग के पौधे

पालमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलॉजी यानी आईएचबीटी ने दो साल के शोध व अनुसंधान के बाद पाया कि पहाड़ी क्षेत्र हींग के लिए माकूल रहेंगे। सबसे पहले 2020 में हिमाचल प्रदेश में हींग के पौधे की खेती शुरू की गई। शोध के दौरान आईएचबीटी के वैज्ञानिकों ने अफगानिस्तान और ईरान से हींग के बीज मंगाए। फिर करीब तीन साल की मेहनत के बाद हींग के पौधे तैयार किए गए। इसके बाद सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के सात गांव में परीक्षण के तौर पर सात किसानों को हींग की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। साल 2020 में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत में सबसे पहले हींग की खेती शुरू की गई। तीन साल बीतने पर किसानों को सफलता मिलती हुई दिख रही है। पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। उम्मीद है कि दो साल बाद इनकी जड़ों से हींग बनाने के लिए रस मिलेगा।

इन पहाड़ी इलाकों में भी हो रही खेती

काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च यानी सीएसआईआर ने पाया कि लाहौल के अलावा लद्दाख, हिमाचल के किन्नौर, मंडी जिले में जनझेली के पहाड़ी क्षेत्रों में भी हींग के पौधे की खेती की जा सकती है। लिहाजा, लाहौल स्पीति के बाद इन इलाकों में भी हींग के पौधे रोपे गए। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, चंबा, पांगी के ऊपरी इलाकों में भी हींग की खेती का परीक्षण किया जा रहा है। अब तक कुल सात हेक्टेयर जमीन पर 47,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर पौधे पनपने में सफल हो गए हैं। सीएसआईआर ने हींग की खेती के लिए ईरान से बीज मंगाया है। दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने ईरान से हींग की नौ किस्में मंगवाई है। ब्यूरो के मुताबिक, पहली बार हींग के इस बीज को भारत लाया गया है।

भारत में पहली बार कौन लाया हींग?

माना जाता है कि हींग भारत में मुगलों के समय में आई थी। हालांकि, इस धारणा के पीछे का आधार हींग का उत्पादन ईरान और अफगानिस्तान में होना माना जाता है। वहीं, कुछ दस्तावेजों के मुताबिक, हींग मुगलकाल के पहले से भारत में मसाले के तौर पर इस्तेमाल होती थी। संस्कृत में इसे हींगू कहा जाता है. हींग के भारत पहुंचने को लेकर कई शोध चल रहे हैं। हो सकता है कि हींग ईरान में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ भारत आई हो। वहीं, ये भी हो सकता है कि भारतीयों ने मुगलकाल से काफी पहले ही ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले व्यापारियों से हींग मंगवाई हो। हालांकि, आयुर्वेद में हींग का कई जगह जिक्र आता है।

आयुर्वेद में कहां है हींग का उल्?लेख?

अष्टांगहृदय में वाग्भट्ट लिखते हैं, 'हिंगु वातकफानाह शूलघ्नं पित्त कोपनम्। कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु।।' इसका अर्थ है, 'हींग शरीर में वात और कफ को ठीक करता है, लेकिन यह शरीर में पित्त के स्तर को बढ़ाता है. यह गर्म होता है और भूख को बढ़ाता हैय़ यह स्वाद बढ़ाने वाला है. अगर किसी को स्वाद नहीं मिल रहा है तो उसे पानी में मिलाकर हींग दें।' चरक संहिता में भी हींग का उल्लेख आता है. लिहाजा, ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि बेशक भारत में हींग पौधे की पैदावार ना होती हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस्तेमाल कई ईसा पूर्व से हो रहा है। आयुर्वेद में हींग को पाचक और पाचन में सहायक मसाला बताया गया है।

मुंह के बल गिरे टमाटर के भाव, रु. 200 से लुढ़कर सीधे रु. 5 पर पहुंचा भाव, किसान बेहाल

नई दिल्ली। एजेंसी

कभी दो सौ रुपये प्रति किलो से ऊपर के भाव पर बिक रहा टमाटर के भाव आज जमीन पर आ गए हैं। एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में बंपर गिरावट देखी जा रही है। टमाटर के भाव एक महीने में 200 रुपये से लुढ़कर सीधे 5 रुपये पर आ गए हैं। जब टमाटर 200 से 250 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा था तो फसल उगाने वाले भी मालामाल हो रहे थे। लेकिन आज इसको उगाने वाले किसान बेहाल हैं। किसानों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। हाल यह है कि कई जगह पर टमाटर 3 से 4 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। किसान अब अपनी फसल को नष्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

इस वजह से गिरे भाव- टमाटर के भाव गिरने की सबसे बड़ी वजह बंपर पैदावार का होना है। इसकी वजह से कीमतों में काफी गिरावट आ गई है। नासिक के कृषि कार्यकर्ता सचिन होलकर के मुताबिक, 'इस तरह के बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए टमाटर और प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ही एकमात्र रास्ता है।' कुछ किसान जो औने-पौने दाम पर ही सही, अपनी उपज बेचने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी लागत का आधा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। एक एकड़ जमीन पर टमाटर उगाने के लिए किसान को 2 लाख रुपये की पूंजी की जरूरत होती है।

अब इतनी हुई कीमत- पुणे के बाजार में कीमतें 5 रुपये प्रति किलो तक गिर गई हैं। वहीं पिंपलगांव, नासिक और लासलगांव की तीन थोक मंडियों में टमाटर की औसत थोक कीमतें पिछले छह हफ्तों में 2,000 रुपये प्रति क्रेट (20 किलोग्राम) से गिरकर 90 रुपये हो गई हैं। कोल्हापुर में, टमाटर खुदरा बाजारों में 2-3 रुपये प्रति किलो पर बेचा जा रहा है, जो लगभग एक महीने पहले 220 रुपये के आसपास था। पिछले कुछ हफ्तों में थोक बाजारों में कीमतों में गिरावट आते ही पुणे जिले की जुन्नार और अंबेगांव तहसीलों के किसानों ने टमाटर की खेती छोड़नी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े थोक टमाटर बाजार पिंपलगांव एपीएमसी में प्रतिदिन लगभग 2 लाख क्रेट टमाटर की नीलामी की जा रही है।

राज्य कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, नासिक जिले में टमाटर का औसत रकबा लगभग 17,000 हेक्टेयर है। इसमें 6 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। लेकिन इस साल टमाटर की खेती दोगुनी होकर 35,000 हेक्टेयर हो गई है। जिसका अनुमानित उत्पादन 12.17 लाख मीट्रिक टन है। के सचिव शरद गोंगडे के मुताबिक, 'जुलाई में, जब पुणे जिले के नारायणगांव बाजार में थोक कीमतें 3,200 रुपये प्रति क्रेट तक पहुंच गईं, तो कई किसानों ने अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद में टमाटर की खेती शुरू कर दी। बंपर पैदावार के बाद उनकी गणना गड़बड़ा गई।'

संस्था 'श्री योगेश्वर' द्वारा झांकी एवं अखाड़ों का प्रदर्शन

इंदौर। राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित संस्था श्री योगेश्वर गत वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, अपनी मातृ संस्था के विचारों - संस्कारों से ओत- प्रोत संस्था का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल राष्ट्र और समाज के लिए दृढ़ संकल्पित है संस्था 'श्री योगेश्वर' सेवा एवं परमार्थ के कार्यों से अपनी विशेष पहचान स्थापित करने में सफल हुई है, इसी श्रृंखला में संस्था राष्ट्रीय विचारों और कार्यों को शहर एवं प्रांत तक प्रसारित करने हेतु मां अहिल्या की नगरी इंदौर की गौरवशाली परंपरा में झांकियों एवं अखाड़ों के साथ भाग ले रही है। अनंत चतुर्दशी पर श्री गणेश विसर्जन चल समारोह में संस्था द्वारा मुख्य रूप से तीन झांकियों का निर्माण किया गया है जिसमें मुख्य रूप से शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का दर्शन कराया गया है दूसरी झांकी में आदिवासी समाज जीवन की झलकियां प्रस्तुत की गई है। तीसरी झांकी में राधा कृष्ण की लीला दिखाई देगी साथ ही दो अखाड़े एवं भजन मंडलियों के वाहन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उपरोक्त जानकारियां संस्था के संचालक गण श्री नारायण जी कुशवाह, गोविन्दजी गेहलोत, सुरेशजी वर्मा ,दीदी ईंदू भास्कर हरीश जी पांडे दीदी सरिता कुनहारे विजय जी धामनिया कैलाश जी बुरा आकाश जी वर्मा हेमंत जी शर्मा नरेंद्र जी राजपूत जितेंद्र जी कानगुने, श्रीकांत जी पंवार मनोज जी ठाकुर विनीत जी सेन,राजू जी साहूकार आदि ने दी।

कोरोना से भी 20 गुना खतरनाक है ये डेडली वायरस 'X', हो सकती है 5 करोड़ मौतें : WHO

Disease X: कोरोना महामारी से दुनिया अभी पूरी तरह से उबरी भी हीं है कि यूके के हेल्थ एक्सपर्ट ने नई बीमारी के दस्तक की आशंका जताई है। इस बीमारी का नाम है डिजीज एक्स (अ्रैी ॅ) है। इस वायरस को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह नया वायरस 1918-1920 के विनाशकारी स्पैनिश फ़्लू की तरह तबाही मचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नई बीमारी का नाम 'डिज़ीज़ एक्स' रखा है। इसे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार चेतवानी जारी कर रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यह नई महामारी कोटोना वायरस की तुलना में 20 गुना ज्यादा धातक है। इस वायरस की चपेट में आने की वजह से कोरोना की तुलना में ज्यादा मौतें होंगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी ने 2020 में दस्तक दी थी और दुनिया भर में इस वायरस ने खतरनाक तबाही मचाई थी। इस वायरस की चपेट में आने से 2.5 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में 10 प्वाइंट्स में समझिए क्या है डिजीज एक्स और कैसे कोरोना से भी ज्यादा है घातक ।

1. डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में केट बिंघम, जिन्होंने मई से दिसंबर 2020 तक यूके के वैक्सीन टास्कफोर्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, ने विश्वास जाता किया कि डिजीज एक्स कोविड-19 की तुलना में काफी अधिक खतरनाक होगा।

2. विशेषज्ञों के मुताबिक डिजीज एक्स की चपेट में आने से लगभग 50 मिलियन तक मौतें हो सकती हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा 'मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए: 1918-19 फ्लू महामारी ने दुनिया भर में कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तुलना में दोगुना है। ऐसे में ये डेडली वायरस ॅ भी दुनियाभर में कुछ ऐसी ही तबाही मचाएगा। डिजीज एक्स को लेकर

बात करते हुए बिंघम ने कहा, 'दुनिया को बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी करनी होगी और रिकॉर्ड समय में खुराक देनी

3. उन्होंने बताया किवैज्ञानिकों ने 25 ऐसे परिवारों को खोज निकाला है जो वायरस की चपेट में है। उनका मानना है कि अभी भी लाखों वायरस की खोज की जानी है और इनमें महामारी में विकसित होने की क्षमता है।

4. उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में 20 मिलियन से अधिक मौतें हुई। हालांकि इस वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक होने में भी कामयाब रहे। डिजीज एक्स कोरोना की तुलना में 67ङ्ग ज्यादा डेडली है। यह वायरस दुनियाभर में धीरे धीरे फैल सकता है। और आने वाले दिनों में इसके मरीज भी सामने आने लग सकते हैं।

5. बिंघम के मुताबिक, वायरस के प्रकोप में बढ़ोतरी का कारण शहरी क्षेत्रों में अधिक लोगों के एकत्रित होने की बढ़ती प्रवृत्ति है।

6. यह कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग तीन-चौथाई उभरती हुई संक्रामक बीमारियां जानवरों में उत्पन्न होती हैं और फिट एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में तब तक फैलती हैं जब तक कि कुछ परिस्थितियों में वे मनुष्यों को संक्रमित न कर दें।'

7. बिंघम के अनुसार, उठाए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों में से एक आवश्यक वित्तीय संसाधनों को आवंटित करना है।' बिंघम ने कहा कोविड 19 वायरस इस डेडली वायरस एक्स की तुलना काफी हल्का वायरस था। हालांकि कोविड़ में भी कई लोगों की जान गई लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इसपर काबू पाया जा सका है।

8. डिजीज एक्स के टीकों के संबंध में, वर्तमान में कोई अनुमोदित टीके उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, बिंघम वैज्ञानिकों द्वारा हर खतरनाक वायरस परिवार के लिए अलग-अलग प्रोटोटाइप टीकों का एक संग्रह विकसित करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीकों पर केवल पहली शुरुआत' ही डिजीज एक्स की विशिष्ट विशेषताओं को लक्षित करने में मदद कर सकती है।

9. बिंघम ने पोर्टफोलियो रणनीति के बारे में बताया कि टीके को वायरस के विभिन्न पहलुओं का मुकाबला करने के लिहाज से तैयार करना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग तरह के टीके अलग अलग तरह के मरीजों के इलाज में कारगर साबित होते हैं।

10. उन्होंने आगे कहा कि विनिर्माण क्षमताएं विभिन्न देशों और क्षेत्रों के हिसाब से अलग होती हैं। कुछ वैक्सीन प्रारूप बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर अन्य वैक्सीन का उत्पादन करना आसान हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें वर्तमान में टीकों की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। चौथा, शोधकर्ताओं को वैक्सीन डिजाइन के लिए नई प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में संभावित रूप से अधिक प्रभावी और कुशल टीके तैयार किए जा सकें।' '

मोबिल 1रू पावरिंग द्वारा पहली बार मोटो जीपी रू भारत का जश्न मना रहा है

रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग टीम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

22 से 24 सितंबर, 2023 तक भारत के 2023 ग्रैंड प्रिक्स के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में डेब्यू करते हुए मोटो जीपी रू भारत के उद्घाटन में मोबिलरू भारत में रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग टीम को टर्बो-पावर कर रहा है। एक्सॉनमोबिल और रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग टीम के बीच वैश्विक साझेदारी का जश्न मनाते हुए, दो सवारों - ऑस्ट्रेलियाई जैक मिलर और दक्षिण अफ्रीकी ब्रैड बाइंडर द्वारा एड्रेनालाईन-पंपिंग प्रदर्शन, जिनके लिए जीतना एक स्वभाव है, जिन्होंने वैश्विक सर्किट स्तर पर अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया है, इनकी KTM RC16 बाइक्स के पूर्ण-दमदार प्रदर्शन का गवाह बनेगा। दोनों राइडर्स अपनी ग्रांड प्रिक्स बाइक्स को मोबिलरू द्वारा सुनिश्चित प्रदर्शन और आत्मविश्वास से संचालित करेंगे। उन्होंने हाल ही में जेपी ग्रीन्स में आयोजित मोबिल कार्यक्रम में प्रशंसकों के साथ अपना उत्साह साझा किया, जहाँ जैक मिलर ने मोबिल सुपर मोटोरू10W-30 को लॉन्च किया था। सिद्ध इंजन सुरक्षा, लंबा इंजन जीवन और बेहतर ईंधन किफायत के साथ, मोबिल सुपर मोटोरू10ॅ-30 बिल्कुल वही है जो देश भर में रोजमर्रा के सवारों को चाहिए। इसके अलावा, उत्पाद पैकेजिंग में अब इसके लेबल पर रेड बुल केटीएम फैक्ट्री रेसिंग टीम का लोगो होगा। मोबिल ब्रांड को बाइक, राइडर ओवरऑल, गैराज और टीम किट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सॉनमोबिल ल्यूब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, विपिन राणा ने कहा: 'हम रेड बुल परिवार के साथ मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी उपस्थिति का और विस्तार कर रहे हैं। फॉर्मूला1 में ओरेकल रेड बुल रेसिंग टीम के साथ हमारी वर्तमान सफल साझेदारी के अलावा, हमने रेड बुल केटीएम रेसिंग टीम के साथ बहु-वर्षीय समझौते के माध्यम से मोटोजीपी में भी प्रवेश किया है। हम केटीएम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने अत्याधुनिक मोबिल ल्यूब्रिकेंट्स और ईंधन की आपूर्ति के माध्यम से टीम की सफलता का हिस्सा बनने के लिए तत्पर हैं।

भारत के सीबीजी रिवोल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है एवरएनवायरो

पूरे देश मे विस्तार करने की बना रहा योजना

सर्कुलर इकोनॉमी के लिए स्मार्ट और स्वच्छ शहरों और वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा देने के सरकार के मिशन को दे रहा बढ़ावा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर में चल रहे स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के अवसर पर, एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट ने मंगलवार को इंदौर स्थित अवंतिका गैस लिमिटेड (एजीएल) की पाइपलाइन में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के इंजेक्शन का उद्घाटन किया। सीबीजी पाइपलाइन इंजेक्शन क्रोमैटोग्राफ के माध्यम से गैस की गुणवत्ता पर नजर रखता है एवं एजीएल की उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। इस उन्नत सुविधा से कम्प्रेशन, ईंधन और परिवहन पर खर्च में कटौती होगी, जिससे शहर में ण्ध्2 उत्सर्जन में काफी हद तक कमी आएगी। यह यूनिट सप्लाई ग्रिड में प्रतिदिन पांच से छह टन गैस डालने की क्षमता रखती है। उद्घाटन समारोह में अवंतिका गैस लिमिटेड, इंदौर के एमडी श्री अनुपम मुखोपाध्याय, एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ श्री महेश गिरधर और गेल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर एवरएनवायरो के श्री गिरधर ने कहा 'माननीय प्रधानमंत्री जी की 'वेस्ट-टू-वेल्थ' पहल एवं जीरो-वेस्ट और सर्कुलर इकोनॉमी के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के तहत, हमने यह अत्याधुनिक तकनीक की स्थापना की है। 550 टन प्रति दिन क्षमता वाला यह बायो-सीएनजी प्लांट्स हमारे शहरों के आने वाले कल के लिए एक नई जीवन शैली को नया आकार देने वाले इनोवेशन को बढ़ावा देता है।''

श्री गिरधर ने आगे कहा 'हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू), एग्रो वेस्ट और एग्रो-इंडस्ट्रियल वेस्ट सहित अलग अलग तरह के फीडस्टॉक के आधार पर पूरे भारत में 100 से अधिक सीबीजी प्लांट स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में पूरे भारत में 1000 मीट्रिक टन का डेली सीबीजी आउटपुट प्राप्त करना है।'

सीबीजी प्लांट्स के विकास की स्थिति:

एवरएनवायरो पहले ही लगभग 2000 करोड़ के महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब राज्यों में लगभग 20 सीबीजी प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सीबीजी का प्रति दिन 320 मीट्रिक टन (टीपीडी) उत्पादन होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष (जुलाई 22 से जुलाई 23) के दौरान, प्लांट ने 1.75 लाख टन से अधिक जैविक कचरा संसाधित किया है, जिससे वित्त वर्ष 23 में 1 लाख टन से अधिक जीएचजी उत्सर्जन (ण्ध्2I) को रोका जा सका है।

देश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में इंदौर सबसे आगे रहा है। यहाँ एवरएनवायरो द्वारा भारत का सबसे बड़े बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जो शहर के कचरे को ऊर्जा में बदल देता है। यह प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित हो रहा है, एवरएनवायरो और इंदौर नगर निगम के बीच साझेदारी ने प्लांट से अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित किया है। ये उपलब्धियाँ रिन्यूएबल एनेर्जी और वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ावा देने और शहरवासियों के लिए स्वच्छ हवा प्रदान करने के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाती हैं। इसके अलावा, यह प्लांट फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (एफओएम) उत्पन्न करता है जो मिट्टी के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग इको-फ्रेंडली उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, जिससे रिजनरेटिव कृषि को बढ़ावा मिलता है। बायो-सीएनजी प्लांट्स का प्रभाव इंदौर से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर फैला हुआ है जो कम्युनिटी और राष्ट्र दोनों को योगदान देगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।